प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

27.05.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

'' मुख्य समाचार''

- विमल नेगी मृत्यु मामले में सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज की एफआईआर–तीन सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक साल में बदली जाएंगी 20 साल पुरानी मशीनें।
- प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने पीड़ित को समयबद्ध व संतोषजनक न्याय प्रदान करने पर दिया बल।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 जून को किया जाएगा प्रदेश व्यापी भूकम्प मॉक अभ्यास।

सीबीआई

बहुचर्चित विमल नेगी मृत्यु मामले में सीबीआई ने दिल्ली में एफआईआर दर्ज की है। हाईकोर्ट के आदेशों पर अब ये मामला न्यू शिमला पुलिस थाना से सीबीआई दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया गया है। सीबीआई ने विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा एक सौ 8 और 3 की उपधारा 5 के तहत ये मामला दर्ज किया है। सीबीआई के डीएसपी बृजेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में बनी तीन सदस्यीय एस.आई.टी. इस मामले की जांच करेगी।

ज्ञापन

इस बीच विमल नेगी मामले को लेकर प्रदेश भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में शिमला में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपेगा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की वर्तमान स्थिति विशेषकर चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पर पुलिस प्रशासन के रवैए को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह प्रभारी संजय टंडन, सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे।

भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कल 11रू00 बजे नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा। ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी जी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत जो माननीय उच्च न्यायालय ने सीबीआई की जांच के आदेश दिए हैं उस पर सरकार के पुलिस प्रशासन के रवैए को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।

सीपीआईएम

इधर सीपीआईएम ने राज्य सरकार से विमल नेगी मौत मामले में निष्पक्ष व न्यायिक जांच की मांग की है। सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान और राकेश सिंघा ने आज शिमला में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। संजय चौहान ने कहा कि विमल नेगी मृत्यु मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए तभी उनके परिवार को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष न्यायिक जांच होने से एचपीपीसीएल में फैले भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी होगा।

न्यायिक जांच हो ,जो न्यायपालिका जो चाहती है जो ऑफिसर्स उनको चाहिए जिस भी एजेंसी से चाहिए, वो उसकी जांच करें अन्यथा आपने हमने सब ने देखा है कि 2017 से लेकर अभी गुड़िया का परिवार जो है और पूरा प्रदेश उस मासूम हत्या के लिए सीबीआई इंक्वायरी के बाद वो जो है अभी प्रश्नचिन्ह लगा है तो इसलिए सीबीआई के ऊपर जो देश और प्रदेश के अंदर प्रश्न चिह्न जो उठे हैं हम आज भी कह रहे हैं कि वाले जी का मसला कोई छोटा–मोटा नहीं है यह पूरे तरीके से देश और प्रदेश की राजसत्ता, कॉर्पोरेट, कंपनियां और जो अफसरशाही का नेक्सस है ये उसका परिणाम है जो भी लोग इसमें सम्मिलित है उनको गिरफ्तार करो तब जाकर जो है विमल नेगी के परिवार को न्याय मिलेगा।

सीपीआईएम ने मुख्यमंत्री को भी इस मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में 20 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों व उपकरणों को एक साल के भीतर बदला जाएगा। शिमला में कल देर शाम आई.जी.एम.सी. शिमला व अटल इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशिलिटी चमियाणा के फैकल्टी सदस्यों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल चमियाणा व टांडा मैडिकल कॉलेज में दो माह के भीतर रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मैडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध ढंग से थ्री टेस्ला एम.आर.आई. मशीनें भी स्थापित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को प्राथमिकता दे रही है और मैडिकल टैक्नोलॉजी पर एक हजार 3 सौ 50 करोड़ रूपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और नर्सों की भर्ती में कोरोना महामारी के समय काम करने वाली नर्सों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और विधायक हरीश जनारथा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

मुख्य न्यायाधीश

प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा है कि पीड़ित को समयबद्ध व संतोषजनक न्याय प्रदान करना ही न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है। सोलन जिला के अर्की में आज नवनिर्मित न्यायिक परिसर का लोकार्पण करने के बाद उपस्थित न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने कहा कि एक संस्थान के रूप में हम सभी को समुचित न्याय प्रदान करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने सभी से समयबद्ध न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सहायता करने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जिला व सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे।

सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल

भारत ने आतंकवाद को पाकिस्तान के समर्थन को वैश्विक स्तर पर उजागर करना जारी रखा है। इसके लिए विभिन्न देशों का दौरा कर भारत ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति से सबको अवगत कराया है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने आज फ्रांस की राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया से मुलाकात की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी दुनिया को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतिम उपाय के रूप में सटीक हमला किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को अभी रोका गया है और पाकिस्तान को खुद को अच्छी तरह से पेश करना होगा। उन्हें आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद को रोकना होगा। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल असेंबली में स्लोवेनियाई राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्क लोट्रिक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामान्य स्थिति से अवगत कराया।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश सहित जनजातीय क्षेत्रों के भूमिहीन लोगों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। किन्नौर जिला की पूह पंचायत में आज वन अधिकार अधिनियम 2006 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पंचायत स्तर पर वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है और वन अधिकार अधिनियम 2006 के माध्यम से स्थानीय लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। इससे पहले उन्होंने पूह ब्लॉक स्तरीय शिकायत समिति के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता की और प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

मॉकड्रिल

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, के सहयोग से आगामी 6 जून को प्रदेशव्यापी भूकंप मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। अभ्यास के दृष्टिगत आज शिमला में सभी हितधारकों के लिए ओरियंटेशन व समन्वय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख सलाहकार मेजर जनरल सेवानिवृत्त सुधीर बहल ने वर्चुअल माध्यम से भूकंप पर आधारित मेगा मॉक अभ्यास की रूपरेखा और कार्य योजना पर विस्तृत जानकारी दी। सुधीर बहल ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों, एजेंसियों व लोगों के बीच समन्वय और तत्परता को परखना व सुदृढ़ बनाना है। उन्होंने कहा कि मेगा मॉक अभ्यास को लेकर 3 जून को टेबल टॉप एक्सरसाइज भी की जायेगी।

जय हिन्द सभा

ऑपरेशन सिंदूर के तहत वीर सैनिकों के सम्मान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी 30 मई को शिमला में एक विशेष कार्यक्रम जय हिन्द सभा का आयोजन करेगी। उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने आज शिमला में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

चूड़धार

प्रदेश के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल चूड़धार मंदिर में श्रद्धालुओं से प्रवेश शुल्क वसूलने के आदेश को हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्य जीव विंग ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। ये निर्णय विभिन्न धार्मिक संगठनों, स्थानीय निवासियों व अन्य हितधारकों की आपत्तियों के दृष्टिगत लिया गया है। इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है।

'' मुख्य समाचार एक बार फिर''

- विमल नेगी मृत्यु मामले में सीबीआई ने दिल्ली में दर्ज की एफआईआर–तीन सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक साल में बदली जाएंगी 20 साल पुरानी मशीनें।
- प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने पीड़ित को समयबद्ध व संतोषजनक न्याय प्रदान करने पर दिया बल।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 6 जून को किया जाएगा प्रदेश व्यापी भूकम्प मॉक अभ्यास।